नव भारत
राष्ट्रीय हिंदी दैनिक 1934 से

5 हरियाणा-दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के आसार

6 मनरेगा खत्म, 'जी राम जी' योजना लागू

7 सकल जीएसटी संग्रह जून में 13.9 प्रतिशत बढ़ा

8 मेक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराया

एक नजर में

जन्मजात नागरिकता के खिलाफ काम करे संसद

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जन्म के आधार पर नागरिकता उनके देश के लिए अच्छी नहीं है और वह इसके खिलाफ जल्द ही संसद में कानून देखना चाहेंगे. श्री ट्रंप ने मंगलवार रात ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को बरकरार रखा है, जो हमारे देश के लिए बहुत बुरा है. हम राष्ट्रपति के समर्थन से संसद में कानून लाकर इसमें बदलाव कर सकते हैं.

गुरुद्वारे गिराने पर भारत ने पाक से मांगा जवाब

नई दिल्ली. भारत ने पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे को गिराए जाने को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है और इस मामले की जांच कराने तथा दोषियों को सजा देने की मांग की है. विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में बुधवार को कहा कि मंत्रालय ने पाकिस्तान के फारूकबाद में ऐतिहासिक, 125 साल पुराने पवित्र गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा साहिब को गिराए जाने के बारे में बेहद परेशान करने वाली खबरें देखी हैं. उन्होंने कहा, हम सिखों के इस सम्मानित धार्मिक स्थल के खिलाफ तोड़-फोड़ की इस बेहद निंदनीय और जानबूझकर की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं.

चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की मांग

नई दिल्ली. तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें बकरीद वाले दिन सहित पूरे राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था. राज्य सरकार का तर्क है कि उच्च न्यायालय अपने समक्ष आयी याचिका के दायरे से बहुत आगे निकल गया है. यह याचिका केवल कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों के वध को रोकने तक ही सीमित थी. उच्च न्यायालय ने गत 27 मई को इस आशय का निर्णय दिया था. पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मछुआरा कल्याण विभाग के सचिव की ओर से दायर इस अपील में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने राज्य के वैधानिक ढांचे के विपरीत निर्देश जारी किये हैं.

एसआईटी को मिला 15 तक और समय

लखनऊ. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को शासन ने और समय दे दिया है. अब विशेष जांच टीम 15 जुलाई तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी. पहले यह रिपोर्ट 30 जून तक देनी थी. जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है. एसआईटी प्रमुख, लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के सदस्यों किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरत्न कुमार के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी थी. प्रारंभिक रिपोर्ट में ही एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और अधिकारियों की मांग की थी.

बस में आग से 8 जिंदा जले

इंदौर की छात्रा समेत 8 की मौत, 21 लोग घायल

नव भारत न्यूज

इंदौर, 1 जुलाई. घर लौटने की खुशी कुछ ही पल में मातम में बदल गई. राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात ऋषिकेश से इंदौर आ रही स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर से टकराने के बाद आग की लपटों में घिर गई. देखते ही देखते पूरी बस धधक उठी और कई यात्री बाहर निकलने से पहले ही आग की चपेट में आ गए, हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल हैं.

मृतकों में इंदौर की इंजीनियरिंग छात्रा भूमि भोर भी शामिल हैं, जबकि शहर की निर्मला गुप्ता का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल सका. हादसा रात करीब ढाई बजे कोलवा थाना क्षेत्र के तनावड़ जीरो पॉइंट पर हुआ. प्रारंभिक जांच में बस के तेज रफ्तार होने और चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रेलर दोनों में आग लग गई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक छह यात्रियों की मौत झुलसने से हुई, जबकि दो ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया. हादसे में इंदौर के मेघदूत नगर निवासी 20 वर्षीय भूमि भोर एलएनटी कॉलेज में इंजीनियरिंग की छात्रा थीं. वह दोस्तों के साथ मसूरी घूमने गई थीं और लौटते समय हादसे का शिकार हो गई. वहीं चारधाम यात्रा से लौट रहीं निर्मला गुप्ता के पति चंद्रप्रकाश को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन निर्मला बस के भीतर ही रह गई. परिजन उनकी तलाश में राजस्थान पहुंच चुके हैं. घायल यात्रियों ने राहत और बचाव कार्य में देरी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बस के शीशे तोड़कर कई यात्रियों को बाहर निकाला, जबकि प्रशासनिक मदद काफी देर बाद पहुंची. सूत्रों के हवाले से दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने भी दावा किया है कि हादसे के दौरान बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल सके. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

घटनास्थल पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बस की डिक्की में सिगरेट के कार्टून रखे होने का दावा किया है. उन्होंने पुलिस को बताया कि इससे आग ने तेजी से विकराल रूप लिया था, मगर पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है मगर इसे भी जांच का हिस्सा बनाया है. दौसा जिला अस्पताल में भर्ती घायलों में कई मध्यप्रदेश के हैं. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं.

इंदौर के कई यात्री घायल...

हादसे में इंदौर के कई यात्री भी घायल हुए हैं. इनमें दिशा, याचिका, नेहा, सुवानंद, प्रदीप, महक, योगानी और चंद्रप्रकाश गुप्ता शामिल हैं. सभी का उपचार दौसा जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है.

मुख्यमंत्री ने दी करोड़ों की सौगात

2.82 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किसानों के खातों में भेजी

494 करोड़ की 629 विकास कार्यों का किया लोकार्पण

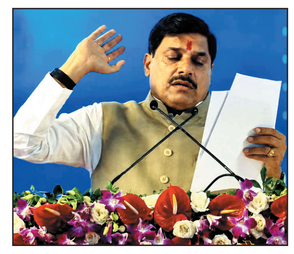

सिवनी, 1 जुलाई. मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिवनी के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव एवं किसान सम्मेलन में जिले को विकास की बड़ी सौगात दी.

इस अवसर पर लगभग 494 करोड़ की लागत के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया तथा प्रदेश के 3,941 कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 2.82 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और श्रीअन्न (मिलेट्स) को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बताते हुए, किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और श्रीअन्न के उत्पादन में वृद्धि करने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिवनी जिले के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी. सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है.

प्रसून जोशी को मिलेगा पहला एनबीटी भूषण सम्मान

नई दिल्ली, 1 जुलाई. प्रख्यात लेखक, गीतकार और पटकथा लेखक प्रसून जोशी को 4 जुलाई को आयोजित होने वाले एनबीटी उत्सव 2026 में पहली बार दिए जा रहे 'एनबीटी भूषण सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा.

साहित्य, संस्कृति, रचनात्मकता और जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं दीर्घकालिक योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से इस सम्मान की शुरुआत की है. प्रसून जोशी को यह सम्मान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान करेंगे.

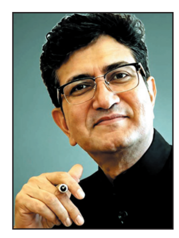

रचनात्मक दुनिया का बड़ा नाम- प्रसून जोशी देश के उन चुनिंदा रचनाकारों में शामिल हैं, जिनकी लेखनी ने सिनेमा से आगे बढ़कर उम्मीद, संवेदनाओं, देशभक्ति और सामाजिक बदलाव की आवाज को अभिव्यक्ति दी है.

भारत और पाकिस्तान ने कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया

नई दिल्ली, 1 जुलाई. भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की जेलों में बंद आम नागरिकों और मछुआरों की सूची का बुधवार को आदान-प्रदान किया. कैदियों की सूची का आदान-प्रदान वर्ष 2008 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए राजनयिक पहुंच समझौते के तहत राजधानी दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया गया. इन सूचियों का आदान-प्रदान हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को किया जाता है.

सुरक्षित पैसे भेज सकते हैं कस्टमर्स

डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार में एक और अहम पड़ाव है

नई दिल्ली, 1 जुलाई. भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधिकारिक तौर पर ग्रीस में लॉन्च हो गया है. केंद्रीय वाणिज्य पीयूष गोयल ने मंगलवार को एथेंस में यूरोबैंक के मुख्यालय में यूरोबैंक और एनआईपीएल की साझेदारी के तहत यूपीआई सेवाओं के लाइव प्रदर्शन को देखा.

इस मौके पर उनके साथ यूरोबैंक के सीईओ फोकियन कारावियास और फेयरफैक्स डिजिटल सर्विसेज के सीईओ संजय तुगनायत भी मौजूद थे. केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि यह लॉन्च भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के वैश्विक विस्तार में एक और अहम पड़ाव है. उन्होंने कहा कि ग्रीस में यूपीआई के शुरू होने से, योग्य ग्राहक तुरंत, सुरक्षित और आसानी से पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं. साथ ही, पैसे हस्तांतरित करने के पारंपरिक तरीकों की तुलना में लेनदेन की लागत भी बहुत कम हो गई है.

व्हाट्सएप के यूजरनाम फीचर पर सरकार की नजर

- ऑनलाइन फ्रॉड की आशंकाओं को लेकर सरकार सतर्क
- नए फीचर के दुरुपयोग और स्कैम रोकने पर फोकस

नई दिल्ली, 1 जुलाई. व्हाट्सएप के नए यूजरनाम फीचर को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है. मोबाइल नंबर साझा किए बिना बातचीत की सुविधा देने वाले इस फीचर के सुरक्षा और गोपनीयता पहलुओं की जांच की तैयारी की जा रही है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार यह आकलन करना चाहती है कि कहीं यह सुविधा साइबर अपराधियों और ऑनलाइन ठगी करने वालों के लिए नया माध्यम तो नहीं बन सकती. हाल ही मेंव्हाट्सएप ने अपना व्हाट्सएप फीचर पेश किया है. इस फीचर के जरिए उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर साझा किए बिना केवल यूजरनेम के आधार पर दूसरे उपयोगकर्ताओं से संपर्क कर सकेंगे. कंपनी का कहना है कि इससे उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता मजबूत होगी और अनजान लोगों के साथ मोबाइल नंबर साझा करने की आवश्यकता कम होगी.

राज्यों के साथ मानसून पर पीएम मोदी ने की समीक्षा

- अल नीनो और कमजोर मानसून पर पीएम सतर्क
- चुनौतियों से निपटने विभागों को सतर्क रहने को कहा

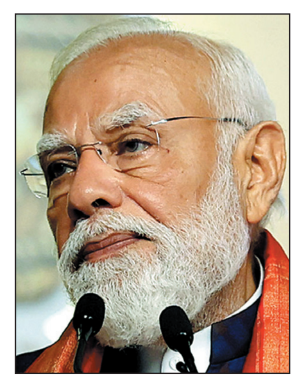

नई दिल्ली, 1 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून की मौजूदा स्थिति और अल नीनो के संभावित प्रभाव को लेकर आयोजित कैबिनेट बैठक में संबंधित मंत्रालयों और राज्यों को अपनी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही भारी वर्षा, संभावित कमजोर मानसून तथा मौसम के बदलते स्वरूप से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की समीक्षा की गई. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सतर्क रहने के लिए कहा है. उन्होंने राज्यों और संबंधित मंत्रालयों को अल नीनो तथा कमजोर मानसून की स्थिति से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति अपनाने पर जोर दिया. बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि विभिन्न राज्यों के साथ निरंतर तालमेल बनाए रखते हुए समय पर आवश्यक कदम उठाए जाएं.

सूत्रों के मुताबिक, अल नीनो के प्रभाव के कारण इस वर्ष मानसून के वितरण में असमानता देखने को मिल सकती है. कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है.

> संभावित मौसमी परिस्थितियों के मद्देनजर बिजली की मांग बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिजली आपूर्ति व्यवस्था, केबलों की मरम्मत तथा रखरखाव जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं. प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि अल नीनो के प्रभाव को कम करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी राज्यों को साझा रणनीति के तहत तैयार रहना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया.

कोई भी व्यवस्था न्यायालय से ऊपर नहीं : हाईकोर्ट

जबलपुर, 1 जुलाई। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने न्यायिक जवाबदेही पर कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यवस्था न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकती।

न्यायालय ने उक्त टिप्पणी उस समय की, जब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन की ओर से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी गई और उनके हलफनामे का स्पष्टीकरण अधिवक्ता द्वारा देने की पेशकश की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन प्रश्नों का संबंध सीधे चेयरमैन के हलफनामें से है, उनका उत्तर उन्हें स्वयं देना होगा। आदेश में अदालत ने दर्ज किया कि प्रस्तुत तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है मानो संबंधित अधिकारी न्यायालय से ऊपर हों, जबकि यह कार्यप्रणाली स्वीकार्य नहीं है। दरअसल यह मामला आयकर अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता की याचिका से जुड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति को चुनौती दी गई है।

कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

- एलपीजी सिलेंडर के दाम 183.50 रुपये घटे
- जून में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये थी

नई दिल्ली, 1 जुलाई. अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के बाद सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बुधवार से रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 2,930 रुपये का हो गया है. जून में इसकी कीमत 3,113.50 रुपये थी. इस प्रकार यहां इसकी कीमत 183.50 रुपये घटायी गयी है. देश के अलग-अलग शहरों में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत और कटौती अलग-अलग है. यह कंपनियों की लागत और अन्य स्थानीय कारकों के हिसाब से तय होती है. वहीं, घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अपरिवर्तित है. दिल्ली में यह 942 रुपये का मिल रहा है. इससे पहले, एक जून को वाणिज्यिक रसोई गैस की कीमत बढ़ायी गयी थी. दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ी थी. देश की राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम सात जून को 29 रुपये बढ़े थे. पश्चिम एशिया संकट के कारण रसोई गैस की आपूर्ति में बाधा के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने पिछले तीन महीने में एलपीजी के दाम में अच्छी खासी वृद्धि की थी.

कैबिनेट बैठक | दो साल में पूरा होगा 242 किलोमीटर का प्रोजेक्ट

कानपुर से भोपाल हाईवे को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, 1 जुलाई. सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर को मध्य प्रदेश के भोपाल आर्थिक गलियारे से जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड राजमार्ग परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की

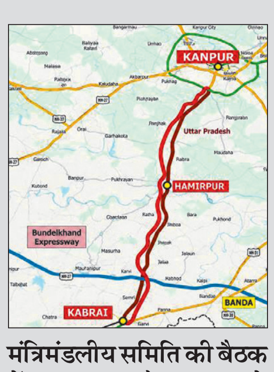

मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर 117.7 किलोमीटर लंबे कानपुर-कबरई खंड को चार लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे भविष्य में छह लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा. परियोजना पर 7,145.14 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. करीब दो साल में 242 किमी का प्रोजेक्ट पूरा होगा.

द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक बनेगी सुरंग

सरकार ने राजधानी दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ने के लिए 6970 करोड़ रुपये की लागत से आठ किलोमीटर लंबी छह लेन की सुरंग बनाने का निर्णय लिया है. द्वारका दिल्ली के बीच तेज कनेक्टिविटी को बढ़ायेगी.

पूरे देश में लागू हुआ वी बी-जी राम जी

- न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300, औसत मजदूरी 327.4
- जानिए ग्रामीण मजदूरों को क्या मिलेगा नया

नई दिल्ली, 1 जुलाई. केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 लागू कर दिया है. नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ग्रामीण रोजगार से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं.

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को नई मजदूरी दरों को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित मजदूरी दरें प्रभावी हो गई हैं. नई व्यवस्था के तहत औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये कर दी गई है. इस प्रकार औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है. इसके अलावा सरकार ने पूरे देश के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, ताकि किसी भी राज्य या क्षेत्र में मजदूरी इससे कम न रहे.

> ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देश के सभी 34 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और वेतन क्षेत्रों में मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है. मंत्रालय का कहना है कि औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी दरों में 15 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. वहीं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है. नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी भी बढ़ा दी गई है. पहले जहां 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है.